

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 12 मार्च, 2008

विषय:- नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन, अल्मोड़ा के साज-सज्जा हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

-----

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 570/यू०एच०सी०/एडमिन-बी./निर्माण/2006, दिनांक 21.02.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन, अल्मोड़ा के साज-सज्जा हेतु प्रेषित आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 28,66,000/- (अठ्ठाईस लाख छियासठ हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान में रु० 3,67,000/- (तीन लाख सरसठ हजार रुपये मात्र) की धनराशि एवं शेष धनराशि शासनादेश संख्या-8-दो(2)/XXXVI(1)/2007-1-दो(2)/07, दिनांक 31.7.2007 द्वारा उपशीर्षक-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में स्वीकृत धनराशि से व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, तो उनके कान्टेक्ट रेट के तीन कोटेशन प्राप्त कर तुलनात्मक विवरण में तीनों दरों को इंगित कर न्यूनतम दर के आधार पर आगणन तैयार करते हुए उस पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त किया जाय ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (4) कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करले कि पर्चेज नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय एवं इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा।
- (5) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।



- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
- (7) फर्नीचर आदि का क्रय मानक के अनुसार किया जाना होगा । आवश्यकता से अधिक फर्नीचर का क्रय किसी भी दशा में न किया जाय ।
- (8) फर्नीचर के क्रय के लिए निविदा आमंत्रण के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे 31.3.2008 से पूर्व राजकोष में जमा किया जाना होगा ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" से किया जायेगा ।
4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-1464/XXVII(5)/2007, दिनांक 11.3.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या : 40-दो(2)/XXXVI(1)(2)/2007-08-1-दो(2)/07-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा ।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
5. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
6. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( आलोक कुमार वर्मा )

अपर सचिव ।